CUSTOMS, EXCISE & SERVICE TAX APPELLATE TRIBUNAL
ALLAHABAD

REGIONAL BENCH - COURT NO.II

Customs Appeal No.70452 of 2022

(Arising out of Order-in-Appeal No.125-128-CUS/APPL/LKO/2022 dated 22/02/2022 passed by Commissioner (Appeals) Customs, Central Excise & CGST, Lucknow)

Shri Bajrangi Agrahari, **.....Appellant**
(Prop. M/s Gungun Traders,
Dhanaura, Barhni, Siddharthnagar)

VERSUS

Commissioner of Customs (Pre.), Lucknow **....Respondent**

(Kendriya Rajaswa Bhawan, Civil Line, Gorakhpur-273001)

APPEARANCE:

Shri Anuj Agarwal, Advocate for the Appellant
Smt Chitra Srivastava, Authorised Representative for the Respondent

CORAM: HON'BLE MR. SANJIV SRIVASTAVA, MEMBER (TECHNICAL)

FINAL ORDER NO.70341/2025

DATE OF HEARING : 20 May, 2025
DATE OF DECISION : 20 May, 2025

SANJIV SRIVASTAVA:

This appeal is directed against Order-in-Appeal No.125-128-CUS/APPL/LKO/2022 dated 22/02/2022 passed by Commissioner (Appeals) Customs, Central Excise & CGST, Lucknow. By the impugned order Commissioner (Appeals) has upheld the order made against the appellant with regards to order of the confiscation of the Nepali Peas and penalty imposed upon him.

2.1 On 30.10.2019 at about 17:40 hrs SSB Officers intercepted two persons Shri Javed Alam S/o Shri Mohammad Akaram and Shri Bajrangi Agrahari S/o Late Lalla Prasad Agrahari near at Indo-Nepal border pole no.567/1 from 30 meters away to no man's land area at Ram Lila field in Bolero

pickup No.UP55T9123 along with 33 bags of while peas weighting 1650 kgs, which was being loaded. The persons alongwith the said peas were handed over to the Customs Authorities.

2.2 After completion of the investigations in the matter, show cause notice dated 30.10.2019 was issued to the appellant and others asking them to show cause as to why-

> *"(i) अभिग्रहीत उपरोक्त वर्णित मटर 1650 किग्रा० सीजर मूल्य Rs.82500/- को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की क्रमशः धारा 111 (बी) एवं (डी) के अन्तर्गत अभिग्रहीत कर लिया जाय और उन्मुक्ति आदेश के अनुपालन में टी० आर-6 द्वारा सरकारी कोष में जमा धन राशि Rs.412507/- को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 126 के अन्तर्गत समायोजित कर लिया जाय।*
>
> *(ii) उपरोक्त अभिग्रहीत बोलेरो पिकप संख्या UP55T9123 मूल्य रु० 4,00,000/- को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 115 (2) के अन्तर्गत अभिग्रहीत कर लिया जाय। और उन्मुक्ति आदेश के अनुपालन में टी० आर०-6 द्वारा सारकारी कोष में जमा धन राशि रू0 100000/-को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 126 के अन्तर्गत समायोजित कर लिया जाय।*
>
> *(iii) और श्री बजरंगी अग्रहरि (माल स्वामी) श्री जावेद आलम (चालक) श्री राजेश (वाहन स्वामी) एवं श्री पिन्टु अग्रहरि (गोदान स्वामी) पर उपर्युक्त अधिनियम एवं अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण अधिनियन की धारा 112 के अन्तर्गत जुर्माना लगाया जाय।"*

2.3 The said show cause notice was adjudicated as per the Order-in-Original dated 13.04.2021 by holding as follows:-

"आदेश

> *1. मैं, अभिग्रहीत (seized) 1650 किलोग्राम नेपाली मटर, मूल्य रूपया 82,500/- (बयासी हजार पांच सौ रूपये मात्र) जैसा कि पंचनामा दिनांक 30.10.2019 में उल्लिखित है, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा ।।। के अंतर्गत अधिहरण (confiscation) करने का आदेश देता है फिर भी मैं उक्त अभिग्रहीत (seized) 1650 किलोग्राम नेपाली मटर के स्वामी को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 125 के अंतर्गत रुपया 41,250/- (रुपया इकतालीस हजार दो सौ पचास मात्र) विमोचन शुल्क अदा करने पर उक्त सामान वापस प्राप्त करने का अवसर देता हूँ। चूंकि 1650 किलोग्राम नेपाली मटर की सामयिक उन्मुक्ति (provisional release) विधिक स्वामी के पक्ष पहले ही की जा चुकी है, अतः सामयिक उन्मुक्ति के समय जमा की गयी धनराशि रु 41,250/- को विमोचन शुल्क*

से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 126 के अंतर्गत समायोजित किये जाने का आदेश देता हूँ।

2. मैं, अभिग्रहीत (seized) वाहन बोलेरो पिक-अप पंजीयन संख्या UPSST9123 मूल्य रु० 4,00,000/-(रूपये चार लाख मात्र) को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 115 (2) के अंतर्गत अधिहरण (confiscation) करने का आदेश देता हूँ तथा वाहन के विधिक स्वामी को रू 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) विमोचन शुल्क (Redemption Fine), अदा करने पर वाहन को विमोचित (Redeem) करने का विकल्प देता हूँ। चूंकि वाहन की सामयिक उन्मुक्ति (provisional release) विधिक स्वामी के पक्ष में पहले ही की जा चुकी है अतः सामयिक उन्मुक्ति के समय जमा की गयी धनराशि रु 1,00,000/- को विमोचन शुल्क में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 126 के अंतर्गत समायोजित किये जाने का आदेश देता हूँ।

3. मैं, श्री बजरंगी अग्रहरि (माल स्वामी) प्रोपराइटर मेसर्स गुनगुन ट्रेडर्स पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत रू 10,000/- (रुपया दस हजार मात्र), श्री जाबेद आलम (चालक) पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत रू 5,000/- (रुपया पांच हजार मात्र), श्री राजेश (वाहन स्वामी) पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत रू 5,000/- (रुपया पांच हजार मात्र) / एवं श्री पिन्टु अग्रहरि (गोदाम स्वामी) पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत रू 1,000/– (रूपया एक हजार मात्र) का व्यक्तिगत जुर्माना (शस्ति) लगाने का आदेश देता हूँ।"

After issuance of the order, a corrigendum to the order was issued stating as follows:-

"*<u>शुद्धि पत्र</u>*

सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक मण्डल, गोरखपुर द्वारा जारी आदेश संख्या 02/CUST/2021-12 दिनांक 13.04.2021 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

<u>पेज सं० 10 पर अंकित आदेश के क्रम सं० ०। में लिखित पैरा:</u>

"फिर भी मैं उक्त अभिग्रहीत (seized) 1650 किलोग्राम नेपाली मटर के स्वामी को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 125 के अंतर्गत रुपमा 41,250/- (रुपया इकतालीस हजार दो सौ पचास मात्र) विमोचन शुल्क अदा करने पर उक्त सामान बापत प्राप्त करने का अवसर देता है। चूंकि 1650 किलोग्राम नेपाली मटर की सामयिक उन्मुक्ति (provisional release) विधिक स्वामी के पक्ष पहले ही की जा चुकी है, अतः सामयिक उन्मुक्ति के समय जमा की गयी धनराशि रु 41,250/-

को निमोषन शुल्क से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 126 के अंतर्गत समायोजित किये जाने का आदेश देता है।" को निम्नलिखित पढ़ा जाये:

"फिर भी उक्त मटर के स्वामी को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 125 के अंतर्गत रुपया 8500/- (रुपया आठ हजार पाँच सौ मात्र) विमोचन शुल्क तथा देय आयात शुल्क(import duty) एवं अन्य सभी शुल्क(all applicable charges) रुपया 31,769/- (रुपया इक्यावन हजार सात मौ उनहत्तर मात्र) अदा करने पर उक्त सामान वापस प्राप्त करने का अवसर देता है। चूंकि उक्त मटर की सामयिक उन्मुक्ति (provisional release) विधिक स्वामी के पक्ष में पहले ही की जा चुकी है, अतः सामयिक उन्मुक्ति के समय जमा की गयी धनराशि रु 41,250/- को विमोचन शुल्क रुपया 8,500/- से तथा शेष धनराशि रु 32,750/- को देय आयात शुल्क एवं अन्य सभी शुल्क से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 126 के अंतर्गत समायोजित किये जाने का आदेश देता हूँ तथा देय आयात शुल्क एवं अन्य सभी शुल्क से समायोजित करने के पश्चात बच रही शेष धनराशि रु० 19,019/- को उक्त मटर के विधिक स्वामी को जमा करने का आदेश देता हूॅ।"

2.4 Aggrieved appellant and others have filed appeal before Commissioner (Appeals) which has been disposed of as per the impugned order.

2.5 Aggrieved by the impugned order only appellant have filed this appeal as penalties imposed on all others have been set aside along with confiscation of the vehicle.

3.1 I have heard Shri Anuj Agarwal learned Counsel appearing for the appellant and Smt Chitra Srivastava learned Authorised Representative appearing for the revenue.

4.1 I have considered the impugned orders along with the submissions made in appeal and during the course of argument.

4.2 Impugned order records as follows for holding against the appellant:-

"Shri Jawed Alam, the appellant No 1, Shri Pintu Agrahari, the appellant No.2 and Shri Rajesh Kumar, the appellant no.4 have submitted that there is no evidence on record to suggest that the appellants had any prior knowledge or reason to believe that the seized goods were offending in nature and liable for confiscation and no person during the investigation has ever stated that appellant had any involvement in the alleged act of smuggling. The appellant

No.3, Shri Bajrangi Agrahari, has submitted that the department failed to adduce any cogent and positive evidence in support of allegation that the said goods were smuggled one.

I find that the recovery of the Nepali origin peas from the vehicle No.UP55-T-9123 has not been disputed as Shri Jawed Alam (Driver of the vehicle) and Shri Rajesh Kumar (Owner of the vehicle), accepted the same vide their statement recorded U/s 108 of the Customs Act, 1962. I find that Shri Jawed Alam, the appellant no.1 vide his statement dated 11.11.2019 stated that he is part time driver of the said vehicle and loaded the said 33 bags of Nepal origin peas as per the direction of the owner of the goods Shri Bajrangi Agrahari. I find that Shri Rajesh Kumar, the appellant No.4 in his statement dated 18.12.2019 admitted that he has given the said vehicle to Shri Bajrangi Agrahari on freight of Rs. 3000/- but told him not to load any illegal consignment on his vehicle. He further stated that he has no knowledge that in his vehicle Nepal origin peas has been loaded which was illegally imported from Nepal through unauthorized routes. I also find that despite various summons issued to Shri Bajrangi Agrahari, the appellant No.3, he never came forward to tender his statement U/s 108 of the Act, ibid and did not co-operate in investigation proceedings. Further, the statement dated 11.11.2019 of Shri Surendra Kumar Kanojia, Mandi Assistant, Agriculture Production Mandi Committee Shohratgarh reveals that gate pass No.2066803 dated 30.10.2019 was issued by him after due verification of the goods declared by M/s. Gungun Traders, as there is no difference between the Nepali peas and Indian peas, and issued the gate pass. He did not know the said consignment was of foreign Nepali origin. Thus, I find that the documents submitted, at the time of seizure, is for the onwards transportation of the said consignment only to cover the same in disguise of Indian Peas. Thus, I find that the said consignment was rightly

seized under Section 110 of the Act, ibid. From the facts of the case as discussed above, it can safely deduce that the adjudicating authority has rightly confiscated the said goods for violating the provisions of Section 11 of the Customs Act, 1962 read with Notification No.9/96-CUS(N.T.) dated 22.01.1996, Section 7(1)(c)of the Customs Act, 1962 & Notification No.63/94-CUS(N.T.) dated 21.11.1994 and given the option to redeem the same after paying the fine in lieu of confiscation as provided U/s 125 of the Customs Act, 1962. …………………………………………………..

In respect of Bajrangi Agrahari, I find that he is the one who is fully involved in the illegal importation of the said consignment as evident from statements of Shri Jawed Alam and Shri Rajesh Kumar and escaped from co-operation in the proceedings, thus, the adjudicating authority has rightly imposed the penalty invoking the provision of Section 112 of the Custom Act, 1962 against him in the impugned order. Therefore, I do not wish to interfere with the same."

4.3 I find that the goods under confiscation were intercepted within India territory i.e. Ram Leela Maidan near Indo-Nepal border. Further, in the show cause notice itself following has been recorded:-

"सुरेंद्र कुमार कनौजिया पुत्र स्व0 राम आसरे कनौजिया, मंडी सहायक कृषि उत्पादन मन्डी समिति, सोहरतगढ़ की उपडी बढ़नी सिद्धार्थनगर नै सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 108 के अन्तगर्त दिनांक 11.11.2010 को अधीक्षक सीमा शुल्क निवारक इयाई बढ़नी जिला सिद्धार्थनगर के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान (बयान की फोटो प्रति संलग्नक-8 रूप में संलग्न हैं) में बाताया कि एस०एस०बी० बढ़नी के अधिकारियों द्वारा सुपूर्त गेटपास संख्या 2006803 दिनांक 30.10.19 उससे विभाग का प्रपत्र है। उक्त गेटपास संख्या 2006803 दिनांक 30.10.19 मेरे द्वारा जारी किया गया है। और मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि ये मटर विदेशी है। मुझे देशी एवं विदेशी मटर में कोई फर्क नजर नहीं आया। इसीलिए मेरे द्वारा गेट पास जारी किया गया। यदि मेरे संज्ञान में आता कि मटर विदेशी है तो किसी भी स्थिति में उसके द्वारा पेट पास जारी नहीं किया जाता। गेट पास जारी करने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर बताया कि सर्वप्रथम व्यापारी

द्वारा 6 आर बाउचर से जिन्स कय किया जाता है। एवं विकी हेतु 9 R जारी किया जाता है। 9आर के साथ प्रपत्र 5 आर (ग्रेट पास आवेदन पत्र) भर के 9 आर संलग्न कर प्रस्तुत किया जाता है। जिसके कम में सम्बंधित कर्मचारी स्वयं मौके पर जाकर सत्यापान करता है। जिसके पश्चात् गेटपास जारी किया जाता है। साथ ही साथ बताया कि गाँव धनौरा बिजरा, पो० बढ़नी, जिला सिद्धार्थनगर के पते पर मेसर्स गुनगुन ट्रेडर्स को नाम से उसके विभाग में दर्ज है। जिसके प्रोपाइटर श्री बजरंगी अग्रहरि पुत्र श्री लल्ला प्रसाद अग्रहरि, गाँव धनौरा बिजरा, पी० बहुली जिला सिद्धार्थनगर। साथ यह भी बताया कि उक्त फर्म का इक्सटेंसन काउन्टर है जो पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है। परन्तु मेसर्स गुनगुन ट्रेकर्स के प्रोप्राइटर श्री बजरंगी अग्रहरि पुत्र श्री लल्ला पंसाद अग्रहरि ने चदट्टी बाजार बढ़नी ने एक किराये का गोदाम ले रखा है। मकान मलीक एवं गैसर्स गुनगुन ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर श्री बजरंगी अग्रहरि पुत्र श्री लल्ला पंसाद अग्रहरि गाँव धनौरा बिजरा, पो० बढ़नी, जिला सिद्धार्थनगर के बीच एक बहत्यी इकरारनामा हुआ है। जिसकी प्रमाणित फोटो कापी प्रस्तुत किया है। गोदाम के सीमा से दूरी सम्बंधी सरकुलर के बारे मे पूछे जाने पर बताया कि गोदाम भारत नेपाल सीमा से भारतीय क्षेत्र में 35 से 40 मीटर दूरी पर है। परन्तु विभाग के पास गोदाम भारत नेपाल सीमा से भारतीय क्षेत्र में कितनी दूरी पर होना चाहिए सम्बंधी कोई सरकुलर नहीं है। कृषि उत्पादन मन्डी समिति, सोहरतगढ़ बढ़नी सिद्धार्थनगर के परिक्षेत्र का उत्पादित जिन्न जैसे मटर गेहूँ आदि का अपना सर्व रिपोर्ट है एवं डांटा नागने पर बताया कि इसका कोई बाटा विभाग के पास नहीं है। मंडी समिति परिक्षेत्र में कितनी स्थाीिय मटर की पैदावार होती है एवं मण्डी में कितनी मडर आती है के बारे में बताया कि स्थानीय सदर की पैज्ञातार का रिकार्ड एवं सहन समिति द्वारा तयार नहीं किये जाते हैं। परन्तु उसके विभाग द्वारा व्यापारियो की उपलब्ध कराये गये बाजचर । आर के माध्यम से व्यापारियों द्वारा खरीदी गयी मटर ही मंडी समिति का डेटा है। जिसे गेटपास जारी करने से पूर्व व्यापारी विभाग को प्रस्तुत करता है। उसी 06 आर के आधार पे स्टाक रजिस्टर-44अ में दर्शाया जाता है। मंडीसनिति का अपना मटर का कोई सर्वे रिपोर्ट है और न ही कोई डेटा है। सुरेन्द्र कुमार कनौजिया ने उक्त फर्म द्वारा अवधि दिनांक 01/10 19 से दिनांक 30.10.19 तक का प्रस्तुत की गयी 6 आर की प्रमाणित फोटो कापी एवं सम्बधित रजिस्टर की प्रनाणित फोटो कापी मांगने पर 6 आर की प्रमाणित फोटो कापी एवं सम्बंधित रजिस्टर की प्रमाणित फोटो कापी प्रस्तुत किया। मेकर्स गुनगुन ट्रेडर्स किस किस जिन्स की कहाँ कहाँ एवं किस किस से खरीदारी करती है. के बारे सुरेन्द्र कुमार कनौजिया ने बताया कि उपरोक्त फर्म के स्वामी ही बता सकते है। 08 आर जिसे प्रमाणित भी किया गया है. में दर्शाये गये विकलाओं के नाम व पते पर विक्रेताओं से

पत्राचार/उनका भौतिक सत्यापन किया जाना सम्भव है के बारे में पुछने पर दताया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत 06 आर जिसे उसके द्वारा प्रमाणित भी किया गया है. में दर्शाये गये विकताओं के पूर्ण नाम व पता न दशयि जाने के कारण सम्बंधित तिकेताओं से पत्राचार/उनका भौतिक सत्यापन किया जामा सम्भव नहीं है। और त ही 06 आर में दर्शाये गये विकताओं के नाम व पता पर पक्षाचार किया जा सकता है। विभाग में पजीकृत उपरोक्त पार्न ने नेपाल से मटर लाकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 06 आर में भारत के स्थानीय विक्रेताओं का नाम बिना बलदिवत्त व अपूर्ण पता दर्शाकिर विभाग के प्रपन्न जैसे आर. 9 आर 5 आर एवं गेटपास का उपयोग कर भारत में बेचा जा रहा है. कारण पुछने पर स्पष्ट किया कि उसके विभाग द्वारा लाइसेंस धारको को उपलब्ध करायी गयी प्रपत्र है. 6आर में विक्रेता का नाम व पूरा पता के सामने खाली स्थान विक्रेता का नाम व पूरा बता मूरने के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है। यदि ये विक्रेता नाम व पूर्ण पता नहीं वहाँ रहे है तो लाइसेंस धारक इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों कि विभाग ने प्रपक्ष आर में विक्रेता के नाम व पूरा पता लिखाने के लिए खाली स्थान छोड़ रखा है। इस कमी को नोट किया है और कृषि उत्पादन मन्नी समिति, सोहरतगढ़, उप मंडी बढ़नी, सिद्धार्थनगर में पजीकृत लाइसेंस धारको को उपरोक्त प्रपक्ष जैसे 06 आर आदि में विकेता का नाम व पूरा पता भरने के लिए कहेगा। आगे यह बताया कि उपरोक्त गेट पास दिनांक 30.10.19 फर्म मेसर्स गुनगुन ट्रेडर्स धनौरा बिजरा, पो० बढ़नी, जिला सिद्धार्थनगर के प्रपत्र 6 आर 5 आर एवं 9आर के आधार पर जारी किया गया था। जिसकी प्रमाणित फोटो कापी प्रस्तुत है। तथा <u>उसे इस तरह की कोई जानुकारी नहीं थी कि ये मटर विदेशी है। उसे देशी एवं विदेशी मटर में कोई फर्क नजर नहीं आया। इसी लिए उसके द्वारा गेट पास जारी किया गया। यदि उसके संज्ञान में आता कि मटर विदेशी है तो किसी भी स्थिति में उसके द्वारा गेट पास जारी नहीं किया जाता</u>।"

4.4 From perusal of the above statement made by Shri Surendra Kumar Kannojia, Market Assistant states that it was not possible to distinguish between the peas of Indian or Nepali origin. Hence, I do not find any evidence brought on record by which it can be said that the said peas were the peas of Nepali origin. Further, I find that these goods are not even specified under Section 123 of Customs Act and hence the burden to prove the smuggled nature of these goods is squarely on the departmental authorities. Kolkata Bench of this Tribunal in the

case of Shri Rahul Kumar & others Final Order No.75955-75959/2025 dated 23.04.2025 have held as follows:-

"15. Admittedly, when the truck and the car were intercepted, the truck was found to be loaded with 6718.5 kgs of Black Pepper and 3918 kgs of Peas, without any proper documents. Also admittedly the interception and seizure took place at Muzaffarpur, that is well within the Indian region in Bihar.

16. The statutory provision enabling the Customs Officials to intercept, check, verify, detain, seize are all guided by Section 123 of the Customs Act 1962. It would be important to go through the relevant provisions, which are extracted below :

Section 123 in the Customs Act, 1962

123. Burden of proof in certain cases.

(1) Where any goods to which this section applies are seized under this Act in the reasonable belief that they are smuggled goods, the burden of proving that they are not smuggled goods shall be-

(a)in a case where such seizure is made from the possession of any person,-

(i)on the person from whose possession the goods were seized; and

(ii)if any person, other than the person from whose possession the goods were seized, claims to be the owner thereof, also on such other person;

(b)in any other case, on the person, if any, who claims to be the owner of the goods so seized.

(2) This section shall apply to gold, and manufactures thereof, watches, and any other class of goods which the Central Government may by notification in the Official Gazette specify.

17. A careful reading of the above provisions clarifies that the goods in question pertain to,

(a) Gold

(b) Watches

(c) Any other class of goods which the Central Govt may notify,

the officials, can have a reasonable belief and take up the further proceedings. In these cases, the burden to prove the non-foreign nature of the goods is on the person from whose possession the goods are recovered.

18. On the other hand, if the goods in question are not notified by the Central Govt., then the burden entirely shifts to the Customs Officials so as to prove that the goods are of foreign origin.

19. On a specific query from the Bench to the Revenue as to whether Black Pepper and Peas have been so notified, the Ld A R makes the following submissions :

> *Indo Nepal Treaty of Trade 2009 , issued by Ministry of Commerce and Industry.*
>
> *ll. With Reference to Article II*
>
> *1- lt is understood that all goods of Indian or Nepalese origin shall be allowed to move unhampered to Nepal or India respectively without being subjected to any quantitative restrictions, licensing or permit system with the following exceptions:*
>
> *(a) Goods restricted for export to third counties,*
>
> *(b) Goods subject to control on price for distribution or movement , within the domestic market, and (c) Goods prohibited for export to each other's territories to prevent deflection to third countries*
>
> *The said consignment was intercepted on 28.05.2019 near lndo- Nepal border*
>
> *In this regard, reference is relied upon the written reply given in the Lok Sabha by the Minister of Commerce and Industry Shri Piyush Goyal, as per press release dated 03.07.2019, wherein he has categorically stated, interalia that :*
>
> *"India is not importing pepper from Bangladesh Bhutan and Nepal. The various steps taken up by the*

Government to curb import of pepper from Vietnam and Srilanka is as follows ……"

Further, reference is relied upon the written reply given in the Lok Sabha by the Minister of Commerce and Industry Shri Piyush Goyal, as per press release dated 04.12.2019, he has categorically stated, inter-alia that :

In order to reduce the import of pepper and to stabilize the domestic price of pepper, Government has fixed the CIF value of Rs.500 per kg. as the Minimum Import Price (MIP) for black pepper vide Notification of Directorate General of Foreign Trade (DGFT) dated 6/12/2017. Subsequently, an amendmentwas brought in the MIP notification by making import of pepper at or above Rs. 500 per kg. free and import below Rs. 500 per kg prohibited vide DGFT Notification dated 21/3/2018. Some representations regarding smuggling of low priced black pepper from other origin to Indio through Nepal and Bangladesh border were received. In this regard, the field formation of Customs and Directorate of Revenue Intelligence have been alert and made vigilant at the point of entry in the port to detect and prevent entry of inferior quality pepper, from other counties to India. Customs has booked several cases of attempted smuggling of pepper in the recent past

Source: DGCI&S Kolkata/DLI from Customs provided by the Spices Board of India

20. The above details provided by the Revenue only go on to show that some restrictions have been placed on the Minimum Import Price and the situation is being monitored to curb smuggling of low quality Pepper into India from these countries. In order to attract the provisions of Section 123, and to fasten the burden on the person possessing the goods, the items in question, that is the Black Pepper and Peas should have been properly Notified

by the Government, which does not seem to be the case here. The statement of the Minister in the Parliament and Press Conference briefings not carry any statutory weight unless the goods are notified. Thus, I take the view that the Black Pepper and Peas are not covered by any Notification and hence they are not subject to the provisions of Section 123.

21. Therefore, the onus to prove that the goods are of foreign origin, is on the Customs Officials. From the Show Cause Notice and Order in Original, it is seen that the Picture of the Gunny / Woven bags are reproduced with the printed matter of "Rose Brand 5MM Jumbo" and "Sanchit Black Pepper 5MM Best Quality". Obviously, these are the Brand Names. The Bags do not carry any details of the manufacturer's name, their address etc. In such a case no assumption can be made about the foreign origin of these goods. There is nothing to suggest that the Customs Officials have made any enquiry to know as to who the owner of these Brands is and where the factories are located. Another way of ascertaining the origin would be to get the goods tested by approved / empanelled Testing Agency to check the quality of the goods to prove as to whether such goods are of Indian or are of foreign origin. I do not see any such attempt has been made by the Customs officials.

22. The next thing to be considered is the place of interception and seizure. Admittedly, the goods were seized at Muzaffarpur. On checking the map and location, I find that Muzaffarpur is located at a distance of about 216 KMs from Bhimnagar [the alleged town via which the smuggling is taking place]. Further, it is stated that the goods have been loaded from a godown at Bhimnagar. As to whether the goods were initially smuggled from Nepal to Bhimnagar, and as to who undertook this work, is not coming out clearly in the proceedings. Even from the recorded statements of various persons including some of the noticees / appellants herein, there is no admittance

from their side that the goods have been procured illegally from Nepal. Therefore, I take a considered view that the Revenue has not been able to prove conclusively that the goods are of foreign origin.

23. Since the Revenue has not been overcome the test of bringing in conclusive proof towards the foreign origin of the goods, going into the detailed investigation process and allegations and findings given in the impugned order would be more of academic interest. Admittedly, prima facie, the documentary evidence brought in by the appellants have been found to be doubtful. But the point in the present case is, unless it is proved that the goods are of foreign origin, the anomalies found in the transactions cannot implicate the appellants under Customs Act provisions, though they might get implicated under other statutory provisions. Illegality or otherwise of other statutory provisions will have no bearing on the Customs Act provisions and hence they cannot come to the rescue of the Revenue in the present case."

4.5 It is also not brought on record as to how any test or opinion of certain experts were taken in the matter for determining the origin of these goods. In absence of any evidence to establish that the impugned goods were illicitly brought from Nepal, I do not find any merits in the impugned order upholding the confiscation of the goods. As I hold that confiscation of the goods could not be upheld, the penalties imposed under Section 112 of the Act needs to be set aside.

4.6 Impugned order lacks merit and needs to be set aside.

5.1 Appeal is allowed.

(Dictated and pronounced in open court)

(SANJIV SRIVASTAVA)
MEMBER (TECHNICAL)

akp